

पहले मुख्य समाचार।

- साठ वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज की बसों में मिलेगी निःशुल्क यात्रा की सुविधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया निर्णय।
- गंगा एक्सप्रेस वे का हरिद्वार तक होगा विस्तार। झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे और सुल्तानपुर में लॉजिस्टिक क्लस्टर बनाने के प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद ने दी मंजूरी।
- छः माह में एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देगी प्रदेश सरकार। मिशन रोजगार के अन्तर्गत नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री ने की घोषणा।
- प्रदेश भर में मनाया जा रहा है ईद-ए-मिलादुन्नबी। लखनऊ सहित कई जिलों में निकाला जायेगा जुलूस-ए-मोहम्मदी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुयी मंत्रिपरिषद की बैठक में चौबीस महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। इसमें एक निर्णय साठ वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने का है। लोक माता अहिल्याबाई मातृ शक्ति योजना के अन्तर्गत साठ वर्ष से अधिक उम्र की महिलायें यूपी रोडवेज की सामान्य बसों में वोटर आईकार्ड या आधारकार्ड दिखाकर निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। जल्द ही इनके लिये विशेष स्मार्ट कार्ड बनाने का कार्य भी शुरू किया जायेगा। सरकार का अनुमान है कि प्रतिदिन करीब अट्ठासी हजार से अधिक महिलायें इस सुविधा का लाभ ले सकेंगी। इस निःशुल्क बस यात्रा योजना का शुभारम्भ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ से करेंगे।

प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में गंगा एक्सप्रेस वे को हरिद्वार तक विस्तारित करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण छः लेन में किया जाएगा, जिसे भविष्य में आठ लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा।

गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक विस्तारित करने के संबंध में सिक्स लेन विस्तार कर अप टू एट लेन मंत्रिमंडल परिषद ने इसको सहमति प्रदान की है। यह 10,761 करोड़ रुपए की लागत से यह बन के तैयार होगा। इसमें खास तौर से जनपद बिजनौर उत्तर प्रदेश से हरिद्वार तक जाने के लिए मुख्य रूप से राष्ट्रीय मार्ग एनएच 34 मेरठ बिजनौर हरिद्वार राष्ट्रीय मार्ग की सुविधा ही उपलब्ध है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण हो जाने से बिजनौर हरिद्वार से सीधे जुड़ जाएगा एवं गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से इसका सुलभ संपर्क प्रदेश की राजधानी से भी होगा।

मंत्रिपरिषद ने सात हजार नौ सौ अड़सठ करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले झांसी लिंक एक्सप्रेस वे और सुल्तानपुर में इंटीग्रेटेड मैनुफेक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर बनाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी। इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत पच्चीस लाख टैबलेट खरीद के प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है।

राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के सम्मानजनक जीवन और उनके अधिकारों की रक्षा के लिये “उत्तर प्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण कल्याण नियमावली-दो हजार चौदह” में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। इसके अन्तर्गत देखभाल न करने वाले या अत्याचार करने वाले बच्चों को अब वृद्ध माता-पिता अपनी सम्पत्ति से आसानी से बेदखल कर सकेंगे।

प्रदेश सरकार ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों, संस्थानों और चिकित्सा विश्वविद्यालयों में इंटर्नशिप करने वाले एमबीबीएस के छात्रों का स्टाइपेंड बारह हजार से बढ़ाकर पच्चीस हजार रुपये कर दिया है। कल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में इससे सम्बन्धित प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी। सरकार के इस निर्णय से सरकारी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों में अध्ययनरत करीब चार हजार इंटर्न चिकित्सकों को लाभ मिलेगा।

भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिकाइड पेमेंट्स इंटरफेस-यूपीआई को कल दस वर्ष पूरे हो गए। वर्ष दो हजार सोलह में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता को सराहनीय बताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में, प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। यूपीआई से लेनदेन की मात्रा में लगभग तेरह हजार गुना वृद्धि हुई है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में मिशन रोजगार के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में तीन हजार पांच सौ बहत्तर युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसमें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कृषि विभाग के लिए चयनित तीन हजार चार सौ छियालीस प्राविधिक सहायक और मंडी परिषद में एक सौ छब्बीस मंडी सचिवों को नियुक्ति-पत्र दिए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार अगले छः माह में एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देगी। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के नौजवानों की दुनियाभर में मांग है।

आज दुनिया आ रही है। जर्मनी आ रहा है। इजराइल आ रहा है। कहता है साहब यूपी के नौजवान को हमारे यहां भेजें। हम भी अपने यहां नौकरी और मुझे अच्छा लगता है जब यूपी के नौजवानों की लोग तारीफ करते हैं। आज दुनिया मांग रही है यूपी के नौजवानों को। 17 के पहले तो यह स्थिति नहीं थी।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चीनी की कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ जनता का ही नहीं, बल्कि भारत की 140 करोड़ जनता का पेट भरने का सामर्थ्य रखता है।

यूपी में चीनी की कमी नहीं। यूपी की एक महीने की कुल खपत है 4 लाख टन चीनी। हमारे पास मौजूद है 28 लाख टन। यानी आप अनुमान करिए 7 महीने की चीनी हमारे पास मौजूद है और हम 15 अक्टूबर से फिर चीनी मिल चालू करेंगे तो 90 लाख टन यानी 900 लाख क्विंटल चीनी का फिर से प्रोडक्शन अपनी चीनी मिलों के माध्यम से यानी इतने बड़े पैमाने पर सामर्थ्य यूपी के पास है।

प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े सभी अस्पतालों को योजना के नियमों और दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि योजना के नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी उन्होंने बताया कि अस्पताल द्वारा अवैध वसूली, फर्जी बिलिंग और नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना लगाने के साथ दंड का प्रावधान किया गया है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी भारत के लोकतंत्र की नींव हैं। अपने लखनऊ दौरे के अंतिम दिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने कल लगभग पांच सौ बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने बूथ स्तरीय अधिकारियों से आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान मतदान बढ़ाने और प्रत्येक पात्र मतदाता तक पहुंचने की अपील की।

बूथ लेवल ऑफिसर भारत के लोकतंत्र की आधारशिला है। हर बूथ लेवल ऑफिसर अपनी पारदर्शिता और कर्मठता के लिए ना केवल अपने बूथ के मतदाताओं के बीच में जाना जाता है बल्कि पूरे भारत में और पूरे विश्व में जाना और माना भी जाता है। भारत के सभी बूथ लेवल ऑफिसर अपनी कर्मठता से जिस तरीके से कार्य करते हैं इसीलिए उनके साथ संवाद स्थापित करना और जितना वो काम करते हैं और उन सुझावों को भी लेना इसी काम के लिए हम लखनऊ आए थे।

प्रदेश भर में आज ईद-ए-मिलादुन्नबी मनाया जा रहा है। यह हजरत मोहम्मद साहब की यौमे पैदाइश का दिन है। इस अवसर पर लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में जुलूस-ए-मोहम्मदी निकाला जायेगा। इसे लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं।

बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बलिया के तुर्तीपार में घाघरा और बदायूं में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार राज्य में सोलह जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव व्यवस्था को मजबूत बनाये रखने के लिये एक हजार छः सौ अट्टारह बाढ़ चौकियां स्थापित की गयी हैं। अब तक चौदह हजार से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इस बीच, मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई स्थानों पर गरज और चमक के साथ बौछारें पड़ने और पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
